क्रम सं॰	सर्किल का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
3.	बिहार	—	2
4.	दिल्ली	—	2
5.	गुजरात	—	1
6.	हरियाणा	1	2
7.	हिमाचल प्रदेश	—	2
8.	जम्मू एवं कश्मीर	—	2
9.	कर्नाटक	—	3
10.	केरल	—	14
11.	मध्य प्रदेश	—	3
12.	महाराष्ट्र	—	3
13.	उत्तर पूर्व	—	—
14.	उड़ीसा	—	—
15.	पंजाब	1	3
16.	राजस्थान	—	6
17.	तमिलनाडु	—	3
18.	उत्तर प्रदेश	—	3
19.	पश्चिम बंगाल	—	—
	कुल:	4	53

निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्र उनके सामने दिए गए डाक सर्किलों के अंतर्गत आते हैं:—

अंडमान एवं निकोबार	—	पश्चिम बंगाल सर्किल
चंडीगढ़	—	पंजाब सर्किल
दादर एवं नगर हवेली	—	गुजरात सर्किल
दमण एवं दीव	—	गुजरात सर्किल
लक्षद्वीप	—	केरल सर्किल
पांडिचेरी	—	तमिलनाडु सर्किल

सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन

376. **श्री ईशदत्त यादव:**
श्री कनकसिंह भोइनसिंह मंगरोला:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या यह सच है कि सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण इन परियोजनाओं को उचित समय पर ठीक से क्रियान्वित नहीं किया जाता है;

यदि हां, तो ऐसे विवादों से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (ग) सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब करवाने वाले, विभिन्न विभागों के बीच विवादों के बारे में केन्द्र को कोई सूचना नहीं मिली है। निजी व वन संबंधी दोनों प्रकार की भूमि का अधिग्रहण करने में आने वाली कठिनाईयों की वजह से ही मुख्यतः परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब होता है।

सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सिंचाई परियोजना में निवेश अनुमति के लिए पर्यावरणीय और/या वन के दृष्टिकोण से स्वीकृति से अनुमति लेना पूर्व-आवश्यकता है। विभिन्न विभागों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत करने से पहले परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों को राज्य स्तरीय बहु-निग्रह एकक स्थापित करने की सलाह दी गई है। अन्तरराज्यीय नदी के जल के बांटने और अन्य राज्यों में आप्लावन जैसे अन्तरराज्यीय मुद्दों वाली परियोजनाओं पर अपनी निवेश अनुमति लेने से पहले राज्य सरकार को संबंधित राज्य सरकारों की सहमति लेने की भी आवश्यकता होती है।

देश में सिंचाई क्षमता

377. **श्री राम जेठमलानी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कुल स्थापित सिंचाई क्षमता का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) मार्च, 1996 तक देश में कुल कितनी सिंचाई क्षमता स्थापित की गई;

(ग) देश में उसमें से कितनी सिंचाई क्षमता का उपयोग करने की क्षमता है;

(घ) क्या यह सच है कि गत दशकों में देश में सिंचाई क्षमता पैदा करने हेतु सरकार द्वारा भारी धनराशि खर्च की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1950 के बाद पैदा की गई सिंचाई क्षमता पर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी हां।

(ख) और (ग) मार्च, 1996 तक देश में कुल संस्थापित सिंचाई क्षमता 89.42 मिलियन हेक्टेयर होने की प्रत्याशा है और मार्च, 1996 तक 79.94 मिलियन हेक्टेयर क्षमता के उपयोग की प्रत्याशा है।

(घ) और (ङ) जी हां। प्रथम पंचवर्षीय योजना से वर्ष 1993-94 तक सरकार द्वारा सिंचाई क्षमता के सृजन पर कुल 49624.47 करोड़ रुपए व्यय किए गये। आठवीं योजनावधि (1992-97) के दौरान 28391.79 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया।

Telephone/STD/Fax facilities in Panchayats

378. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the district-wise number of Panchayats in the country particularly in the State of Punjab as on 30th June, 1996 where telephone, STD, Fax facilities and post offices are available;

(b) the target fixed for the purpose for the next two years;

(c) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) The information is being collected and shall be laid on the table of the House.

(b) The target for providing Village Public Telephones including Panchayat telephones for the year 1996-97 has been fixed at 75,000. Instructions have been issued for covering maximum number of Panchayats. Target for the year 1997-98 is not yet finalised. The plan targets for Post Offices are fixed annually under Annual Plan Schemes only.

(c) Government have adopted National Telecom Policy which envisages provision of a public telephone facility to all the villages including Panchayats by the year 1997 progressively subject to availability of resources. It has also adopted a policy for providing STD facility from such telephones wherever technical feasibility exists. Steps are being taken for providing connectivity through reliable media.

Post Offices are opened under Annual Plan Schemes subject to fulfilment of prescribed norms and availability of resources. During the first four years of the 8th Five Year Plan, 1310 Post offices have been opened in Gram Panchyat areas, and 497 Panchayats Sanchar Seva Kendras have also been opened in the country to provide basic postal facility in those villages where there was no post offices.

Idle Workers of National Textiles Corporation Mills

379. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the total number of idle workers as on date in the mills run by National Textiles Corporation, State-wise;

(b) the expenses incurred on them; and

(c) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) and (b) A statement is enclosed indicating the State-wise details of present strength of idle workforce in the mills run by NTC and the idle wages paid to them. *(See* below)

(c) On account of continuous losses suffered by NTC Mills, 8 out of its 9 subsidiares have been referred to the BIFR which has declared them to be sick Industrial Companies. Government approved a revised modernisation plan for NTC Mills on 9.5.95. This revised Turn Around Plan is generally in line with the modernisation plans prepared by the Textile Research Associations. The plan envisages modernisation of 79 mills at an outlay of Rs. 2005.72 crores, restructuring of 36 unviable mills into 18 viable units, rationalisation of surplus workforce through Voluntary Retirement Scheme etc. The funds for modernisation